


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। हमने धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 22.10.2014 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 27.06.2017 को लगभग 32 माह अर्थात् लगभग 960 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह उज्र लिया है कि प्रार्थी को आराजी की रेकॉर्ड की नकल लेने पर जानकारी हुई कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश लिया हुआ है जिससे प्रार्थी का नाम रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क करने तथा दिनांक 19.06.2015 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में बतौर पक्षकार संयोजित है तथा अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2014 को अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब व काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की आरंभ से ही बखूबी जानकारी थी तथा अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब कारित किया गया है। विलंब के लिए प्रस्तुत कारण सद्भाविक व युक्तियुक्त नहीं हैं। बल्कि विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण घटित हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफी योग्य नहीं हैं।</p> <p>विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>1- 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963- Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.</p> <p>2- 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.</p> <p>3- 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 &amp; 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforesaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or referred to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.</p> <p>4- 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law-then he cannot turn</p>	

तारीख हुक्म 5	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed.</p> <p>हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 960 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 960 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक <b>27.03.2026</b> को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (डॉ० भास्कर बिश्नोई) <b>राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली</b></p>	